भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3088

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

भारतमाला परियोजना का प्रभाव

†3088. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं की राज्य-वार, विशेषकर तमिलनाडु के अरानी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित या उन्नत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है और उनकी अनुमानित लागत और समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतमाला परियोजना के माल ढुलाई दक्षता, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और स्थानीय आर्थिक विकास के संबंध में प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) लंबित परियोजनाओं के समय पर पूरा होने तथा भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि स्थानीय रोजगार, छोटे ठेकेदार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतमाला परियोजना से लाभान्वित हों?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) 5,35,000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से देश भर में 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करने वाले भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण को 2017 में स्वीकृत किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, कुल 26,425 किलोमीटर की परियोजनाओं को सौंपा गया है और इसमें से जून 2026 तक 22,755 किलोमीटर का निर्माण पहले ही हो चुका है। राज्यवार विवरण संलग्न हैं। इसके अलावा, पिछले 3 वर्षों में, भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 6,600 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण किया गया है। अरानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत/पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), बैंगलोर द्वारा भारतमाला परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किए गए अध्ययन से कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। आर्थिक रूप से, घरेलू आय और व्यय में वृद्धि हुई है। लागत में कमी के साथ लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हुआ है। व्यवसायों को बाजारों और कारखानों तक बेहतर पहुंच से लाभ हुआ है। सामाजिक रूप से, स्कूलों और

स्वास्थ्य सुविधाओं तक यात्रा का समय कम हुआ है, जिससे सुगम्यता में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, अध्ययन से पता चलता है कि भारतमाला परियोजना ने सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आईआईएम बैंगलोर द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, भारतमाला परियोजना ने महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदर्शित किए हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं में देरी के मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे/अड़चनें, वैधानिक स्वीकृतियों/अनुमतियों को प्राप्त करने में देरी, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाना, कानून व्यवस्था, निर्माण सामग्री/खनिजों की अनुपलब्धता, ठेकेदार/रियायतग्राही का खराब कार्यनिष्पादन और कोविड-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित घटनाएं हैं। परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। इनमें भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित बनाना, वन और पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से परिवेश पोर्टल का पुनर्गठन करना, रेलवे से रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की ऑनलाइन स्वीकृति सक्षम करना और विभिन्न स्थानों पर समीक्षा बैठकें आयोजित करना शामिल हैं। सरकार ने राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया है। सरकार इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए, केंद्र सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जहां बोलीदाता अपनी तकनीकी और वित्तीय क्षमता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं, की सहायता के लिए अपनी बोली प्रक्रिया में स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है।

भारतमाला परियोजना का प्रभाव के संबंध में श्री थारानीवेंथन एमएस द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3088 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारतमाला परियोजना के लिए राज्यवार प्रगति विवरण

राज्य	**कुल लंबाई (किमी)**	**आवंटित लंबाई (किमी)**	**30 जून 2026 तक निर्मित लंबाई (किमी)**
आंध्र प्रदेश	2,525	1,936	1,560
असम	433	431	415
बिहार	1,572	1,159	816
छत्तीसगढ	571	471	426
दिल्ली	203	203	195
गोवा	26	26	26
गुजरात	1,577	1,194	1,071
हरियाणा	1,058	1,058	1,011
हिमाचल प्रदेश	167	167	117
जम्मू और कश्मीर	433	251	182
झारखंड	1,000	801	557
कर्नाटक	2,059	1,603	1,274
केरल	1,126	708	590
मध्य प्रदेश	3,063	2,017	1,826
महाराष्ट्र	3,029	2,174	2,002
मणिपुर	635	635	572
मेघालय	170	170	153
मिजोरम	593	593	542
नागालैंड	208	208	168
ओडिशा	1,586	967	948
पंजाब	1,764	1,553	885
राजस्थान	2,503	2,360	2,264
तमिलनाडु	2,414	1,476	1,359
तेलंगाना	1,719	1,026	955
त्रिपुरा	94	94	69
उत्तर प्रदेश	3,126	2,495	2,203
उत्तराखंड	273	264	204
पश्चिम बंगाल	874	385	364
कुल	**34,800**	**26,425**	**22,755**

तमिलनाडु राज्य के अरानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों का विवरण

क्र. सं.	एनएच संख्या.	खंड का नाम	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	अरानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई (किमी)	पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण	चल रहे कार्यों का विवरण	स्वीकृत और शुरू किए जाने वाले कार्यों का विवरण
1	नया एनएच-32, एनएच-132 और एनएच-38 (पुराना एनएच-45)	एनएच-32, एनएच-132 और एनएच-38 का टिंडीवनम-उलुंदुरपेट खंड	72.90	10.00	इस खंड का 4-लेन निर्माण कार्य जुलाई 2009 में बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर बीओटी (टोल) मोड के तहत पूरा किया गया था और यह खंड बीओटी रियायतग्राही द्वारा फरवरी 2027 तक संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के अधीन है।	ब्लैकस्पॉट उन्मूलन की दिशा में किलोमीटर 127+880 पर एक लाइट व्हीकल अंडरपास (एलवीयूपी) का निर्माण कार्य प्रगति पर है (पूरा होने की संशोधित निर्धारित तिथि 30.09.2026 है)।	1) सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 126+000 किलोमीटर पर वीयूपी (विस्तृत उपयोग सीमा) - समझौता हस्ताक्षरित। 2) सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 124+670 किलोमीटर पर एलवीयूपी (विस्तृत उपयोग सीमा) - निविदाएं आमंत्रित।
2	नया एनएच-77 (पुराना एनएच-66)	एनएच-77 का टिंडीवनम - कृष्णागिरी खंड	182.18	45.23	सड़क के इस हिस्से को पक्की शोल्डर सुविधा के साथ 2-लेन में अपग्रेड कर दिया गया है और यह काम जुलाई 2024 में पूरा हो गया था। वर्तमान में, यह हिस्सा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत है।	-	-

******